जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

चूरू

Rashtradoot

फोनः- 256906, 256907, फैक्सः- 01562-256908 वर्षः 15 संख्याः 349 प्रभात चूरू, गुरुवार 18 अप्रेल, 2024 पो. रजि. न. चूरू/084/2019-21 पृष्ठ 8 मूल्य 2.50 रु.

19 अप्रैल को 102 संसदीय सीटों पर मतदान होगा

इस दिन 21 राज्यों व केन्द्र शासित क्षेत्रों में 12 लाख मतदान केन्द्रों पर मतदाता अपने वोटिंग के अधिकार का उपयोग कर सकेंगे

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 अप्रैल। सात चरणों वाले लोकसभा चुनाव के 19 अप्रैल को हो रहे प्रथम चरण की वोटिंग को लेकर तैयारियां पूर्ण है। देश के 21 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की 102 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान है। बिहार, उत्तर प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, जम्मू एवं कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिम बंगाल और केन्द्र शासित प्रदेशों के 1.2 मिलीयन मतदान केन्द्रों पर वोट डाल जाएंगे। लोकसभा की 543 सीटों पर लगभग 97 करोड़ मतदाता वोट डालेंगे।

- भाजपा की ओर से नितिन गडकरी, कनीमोई, नकुलनाथ, जतिन प्रसाद, कोयंबटूर से भाजपा अध्यक्ष अन्नामलाई, निशित प्रमाणिक आदि 19 को अपना भाग्य ई.वी.एम. पर आजमायेंगे।
- तमिलनाडू की 39 सीटों व यू.पी. की अस्सी सीटों में से आठ सीटों पर भी मतदान होगा।
- यू.पी. की ये आठ सीटें हैं, सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर व पीलीभीत।
- ये सभी सीटें वैस्टर्न यू.पी. में हैं।
- इस बार के लोकसभा चुनाव में 97 करोड़ मतदाता वोट देंगे।

राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से 12 सीटों पर प्रथम चरण में वोट डाले जायेंगे, मतदान वाली ये सीटें- गंगानगर, चूरू, बीकानेर, झुंझुनूं, सीकर, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, अलवर, भरतपुर, करौली-धौलपुर, दौसा और नागौर है। इन उक्त सीटों में से, चूरू लोकसभा सीट पर रोचक मुकाबला होने की संभावना है क्योंकि कांग्रेस ने इस सीट पर वर्तमान सांसद व भाजपा के पूर्व नेता राहुल कसवां को चुनावी मैदान में उतारा है, इनकी टक्कर भाजपा के उम्मीदवार, भारतीय पैरालंपिक भाला फेंक खिलाड़ी देवेन्द्र झांझड़िया से है। इसी तरह का एक चुनावी मुकाबला नागौर में भाजपा के खिलाफ इंडिया गठबंधन का सामने आया है, जहां पर पूर्व कांग्रेसी सांसद व भाजपा उम्मीदवार ज्योति मिर्धा वर्तमान सांसद व इंडिया ब्लॉक गठबंधन के हनुमान बेनीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं।

2019 के चुनावों में हुए सूपड़ा साफ को रोकने के उद्देश्य से, ज्ञातव्य है कि पिछले चुनावों में भाजपा ने राजस्थान की सभी पर एकतरफा विजय हासिल की थी, अतः इस बार कांग्रेस ने हनुमान बेनीवाल की पार्टी आर.एल.पी. से राजकुमार रोत की भारत आदिवासी पार्टी तथा लेफ्ट पार्टी से चुनाव पूर्व ही गठबंधन कर लिया है। प्रथम चरण में कई दिग्गज नेता प्रत्याशियों का भाग्य ई.वी.एम. में बंद हो जाएगा। इनमें खास नेता, भाजपा के नेता नितिन गडकरी जो नागपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, कोयंबटूर से उम्मीदवार के. अन्नामलाई, जितिन प्रसाद पीलीभीत से, कूच बिहार से निसिथ प्रमाणिक तथा चेन्नई दक्षिण सीट से तमिलसाई सौंदरराजन हैं।

कनिमोई करूणानिधि (डी.एम.के.) से व छिन्दवाड़ा सीट से कांग्रेसी उम्मीदवार नकुल नाथ का भाग्य भी 19 अप्रैल की ई.वी.एम. में बंद हो जाएगा।

प्रथम चरण में तमिलनाडू की समस्त 39 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। भाजपा दक्षिण के राज्यों में अब तक अपना खाता नहीं खोल पाई है हालांकि, इस बार उसे आशा है कि वह कोयंबटूर सीट को जीतने में कामयाब होगी, क्योंकि इस सीट से पार्टी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष व पूर्व आई.पी.एस. अधिकारी के. अन्नामलाई को चुनावी मैदान में उम्मीदवार बनाया है।

उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भाजपा के खिलाफ राजपूतों का विद्रोह

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 अप्रेल। राजपूत समुदाय ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के खिलाफ कम से कम तीन राज्यों में विद्रोह कर दिया है।

उत्तर प्रदेश और राजस्थान गुजरात का सौराष्ट्र क्षेत्र, जहाँ राजपूतों की पहचान क्षत्रिय के रूप में है। यह समुदाय केन्द्रीय मंत्री पुरूषोत्तम रूपाला द्वारा भरे गए नामांकन को वापिस लिए जाने की मांग

- पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान व सौराष्ट्र के राजपूतों ने भाजपा के खिलाफ यू.पी. के मुजफ्फरनगर जिले के एक गांव में एक महापंचायत का आयोजन किया।

कर रहा है। उत्तर प्रदेश के मुज़फ्फरनगर जिले के एक गांव में मंगलवार को आयोजित राजपूतों की एक महापंचायत हुई है, जिसमें स्पष्ट है कि भाजपा इस क्षेत्र में मुश्किल स्थिति का सामना कर सकती है। प्रभावशाली राजपूत समुदाय के "गर्व" एवं "सम्मान" का अचानक से किया गया यह प्रदर्शन वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले चरण के

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दो बार लगातार 25-0 से हारने के बाद कांग्रेस के लिये हैट ट्रिक रोकना बहुत जरूरी

कांग्रेस बाड़मेर, दौसा, चूरू, झुंझुनूं की सीटों पर पॉज़िटिव रिज़ल्ट की आशा कर रही है

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 अप्रेल। राजस्थान के गत दो लोकसभा चुनावों (2014 और 2019) में कांग्रेस की करारी हार हुई थी, जिनमें पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी, पर 2024 के लोकसभा चुनाव का माहौल कांग्रेस के पक्ष में बदलता हुआ लग रहा है। बाड़मेर, दौसा, चूरू और झुंझुनूं में कांग्रेस अच्छा कर रही है, वहां उम्मीद है कि भाजपा हार जाएगी।

इसके अलावा जयपुर ग्रामीण, भरतपुर, कोटा और टोंक में भी कांग्रेस अच्छी टक्कर दे रही है और इनमें से कुछ सीटें भाजपा से छीन भी सकती है। इस बार कांग्रेस को कुछ सीटें जीतने की उम्मीद है।

- कांग्रेस का खुद का आकलन यह भी है कि, जयपुर रूरल, भरतपुर, कोटा तथा टोंक, सवाईमाधोपुर में भी कांटे की टक्कर दे सकती है।
- कांग्रेस का मानना है कि, 10 साल के शासन के बाद, मोदी "एन्टी इन्कम्बैंसी" का शिकार होंगे तथा सचिन पायलट का आक्रामक (अग्रैसिव) प्रचार भी कुछ अच्छे नतीजे की आशा जगाता है। हालांकि यह भी सच है कि, पूर्व मु.मंत्री का फोकस अपने बेटे की सीट पर ही है तथा अन्य सीटों को वो नज़रअंदाज़ कर रहे हैं।
- गहलोत के चुनाव प्रबंधन व प्रचार के कारण ही, उनके पुत्र का चुनाव प्रचार कुछ जीवित सा है, अगर वैभव गहलोत पर ही चुनाव प्रचार की जिम्मेवारी होती तो, शायद चुनाव प्रचार जमने से पहले ही उखड़ जाता।

सूत्रों का कहना है कि इन क्षेत्रों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की छवि का असर कम हो रहा है। दस साल के शासन के खिलाफ बनी सरकार विरोधी लहर का असर नरेन्द्र मोदी की छवि पर पड़ रहा है। इसी के साथ राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में सचिन पायलट के धूआंधार प्रचार ने पार्टी को खोया जनाधार पुनः पाने में भारी मदद की है। अशोक गहलोत का पूरा फोकस तो अपने बेटे के चुनाव प्रचार पर है जो जालोर-सिरोही से चुनाव लड़ रहे

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

तृणमूल कांग्रेस ने अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी किया

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 अप्रेल। तृणमूल कांग्रेस ने आज अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी किया। यह तृणमूल को एक क्षेत्रीय पार्टी के बजाए, उसकी राष्ट्रीय प्रासंगिकता साबित करने की एक विस्तृत कवायद है।

पार्टी का घोषणा पत्र न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों को समर्थन देने का वादा करता है। पार्टी ने सत्ता में आने की स्थिति में पैट्रोलियम पदार्थों की स्थिर कीमतों, देश में गरीबी की सीमा रेखा से नीचे के प्रत्येक परिवार को 10 निःशुल्क एल.पी.जी. गैस सिलैण्डर और सी.ए.ए. के उन्मूलन का भी वादा कर रही है।

आश्चर्य की बात यह है कि ममता बनर्जी ने एक स्थानीय टी.वी. चैनल को दिए एक साक्षात्कार में पराजय जैसी बात की। उन्होंने कहा कि यदि उन्हें जेल भेज दिया जाए तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे उन्हें बढ़त ही मिलेगी।

- इस घोषणा पत्र में ममता बनर्जी की राष्ट्रीय नेता बनने की महत्वकांक्षा का ज्यादा पुट नज़र आया बनिस्पत तृणमूल पार्टी के प्रदेश स्तर की पार्टी होने की सच्चाई के।
- ममता की समस्या यह है कि, वे किसी भी पार्टी से कांग्रेस या मार्क्सवादी पार्टी से कोई सीटों के बंटवारे के बारे में कोई समझौता करने को तैयार नहीं।
- इसी कारण ममता बनर्जी, इण्डिया गठबंधन से लगभग बाहर सी ही हैं।

पार्टी की समस्या यह है कि उसने इण्डिया गठबंधन के साथ सीट शेयरिंग फॉर्मूला करने या बंगाल में सी.पी.आई. (एम.) और कांग्रेस के लिए कोई भी सीट छोड़ने से इन्कार कर दिया था। राष्ट्रीय स्तर पर तो तृणमूल कांग्रेस, इण्डिया गठबंधन से एक तरह से बाहर ही है।

तृणमूल की एक राष्ट्रीय पार्टी बनने की आकांक्षाएं बढ़ रही है, लेकिन इसके बावजूद उसने राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन का खेल खेलने से इन्कार कर दिया। तृणमूल के बंगाल से बाहर चुनाव लड़ने वाले नाम मात्र के प्रत्याशी हैं। इनमें से एक असम के सिलचर से एक और दूसरा उत्तर प्रदेश में है, वह भी अखिलेश यादव की मदद से।

ममता की राष्ट्रीय प्रतिबद्धता का एकमात्र संकेत यह है कि जिस दिन तृणमूल का घोषणा पत्र जारी किया गया, वह स्वयं असम में चुनाव प्रचार कर रही थीं।

इस बीच, इण्डिया गठबंधन की एक अन्य सहयोगी पार्टी ने पूरे देश में विवादित स्थिति पैदा कर दी है कि यदि वह सत्ता में आयी तो भारत के परमाणु अस्त्रों और सारे परमाणु संस्थानों को समाप्त कर देगी।

घोषणा पत्र के अलग घटक सी.पी.आई. (एम.) और कांग्रेस की तर्ज पर ही है, जिनसे बंगाल के लिए चुनाव घोषणा पत्र आधारभूत काम की कमी दिखाई पड़ती है।

दूसरी ओर, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.बी. आनन्द बोस ने शुक्रवार को उत्तरी बंगाल में स्वयं उपस्थित रहना प्रस्तावित किया है। चुनाव आयोग ने राज्यपाल से कहा है कि वह उत्तर बंगाल के निर्वाचन क्षेत्रों में ना जाए क्योंकि ऐसा करना आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होगा।